भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के संबंध में वर्ष 2020-2021 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा ऑडिट रिपोर्ट के साथ वार्षिक एकाउंट्स को लोक सभा/ राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत किये जाने हेतु समीक्षा वक्तव्य

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR), स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। यह देश का शीर्ष और प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संगठन है जो बायोमेडिकल अनुसंधान की योजना, फॉर्मूलेशन, समन्वय, कार्यान्वयन और प्रौन्नत करने का कार्य करता है। यह दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। 1911 में, भारत सरकार ने देश में चिकित्सा अनुसंधान को प्रायोजित और समन्वित करने के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन (IRFA) की स्थापना का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था। आजादी के बाद, 1949 में, इसके कार्यों और गतिविधियों का विस्तार करते हुए सरकार ने IRFA के स्थान पर "भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद" (आईसीएमआर) के रूप में नया नाम दिया। आईसीएमआर द्वारा वर्ष 2020-21 में आरम्भ की गयी कुछ गतिविधियां निम्नवत हैं :

1. आईसीएमआर ने COVID-19 महामारी के प्रत्येक चरण में, जिसमें वायरस को अलग करना (आइसोलेट), नैदानिक प्रयोगशालाओं की स्थापना, किट का विकास और सत्यापन, नीति निर्धारण, डाटा का संग्रह करना और उसका रखरखाव करना, सभी आयु समूहों के लिए रोकथाम और उपचार के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना, टीका विकसित करना और वैज्ञानिक ज्ञान के पेपरों का प्रकाशन आदि में एक अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

2. आईसीएमआर - राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे, जो तब COVID परीक्षण के लिए एकमात्र प्रयोगशाला थी, ने RT-PCR आधारित नैदानिक परीक्षण का मानकीकरण किया। आईसीएमआर - एनआईवी, पुणे ने COVID-19 का प्रथम मामला 30 जनवरी, 2020 को दर्ज किया। मार्च, 2021 तक संपूर्ण देश में COVID-19 परीक्षण की क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई और प्रयोगशालाओं की संख्या 2435 पहुँच गई। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों तथा लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीपों के दुर्गम भू-भागों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए गए थे।

3. बहुत से परामर्शदाता संस्थानों (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान) जैसी बहुत सी सरकारी प्रयोगशालाओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें COVID-19 का परीक्षण शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया था। इसके परिणामस्वरूप देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में COVID-19 जांच प्रयोगशाला चालू कर दी गई। RTPCR अनुप्रयोग के माध्यम से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सहायता से एक सामान्य नमूना रेफरल फॉर्म (एसआरएफ) विकसित और तैनात किया गया था।

4. वास्तविक समय में बीमारी की प्रवृत्ति को समझने के लिए, आईसीएमआर ने राष्ट्रव्यापी COVID-19 परीक्षण डेटा पोर्टल विकसित किया जिसने देश भर में COVID-19 परीक्षण डेटा प्रविष्टि की सुविधा प्रदान की। COVID-19 परीक्षण और प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिए मूलभूत ढांचे की तैनाती के अलावा, 24 सत्यापन केंद्रों की स्थापना करके नैदानिक वस्तुओं के सत्यापन के लिए एक व्यवस्थित मंच विकसित किया गया था। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की कार्यसूची (एजेंडे) को आगे बढ़ाते हुए, आईसीएमआर ने स्वदेशी परीक्षण किटों के 72% को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप एकल RT-PCR परीक्षण की लागत में कमी आई।

5. स्वदेशी निदान आदि के विकास के लिए SARS-CoV-2 के उपयुक्त नमूनों के साथ उद्योग/ अकादमिक जगत की सहायता के लिए दस COVID-19 जैव भंडारण केन्द्र स्थापित किए गए। देश में COVID-19 की रोकथाम और नियंत्रण की गतिविधियों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का मार्गदर्शन करने हेतु COVID-19 पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) का गठन किया गया। COVID-19 महामारी से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए आईसीएमआर का एक त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित किया गया।

6. आईसीएमआर-एनआईवी (राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान), पुणे और भारत बायोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत का पहला निष्क्रिय संपूर्ण-वायरस COVID-19 टीका (COVAXIN) विकसित किया है। वैक्सीन को मानव के उपयोग के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसका उपयोग राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में किया जा रहा है।

7. आईसीएमआर-एनआईई (राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान) ने SARS-CoV-2 संक्रमण की सीमा को मापने और भारत में महामारी की प्रगति को ट्रैक करने के लिए अप्रैल, 2020 और जनवरी, 2021 के बीच में राष्ट्रव्यापी समुदाय आधारित सीरो सर्वे के तीन दौर (राउंड 1: अप्रैल - मई, 2020; राउंड 2: अगस्त – सितंबर, 2020; राउंड 3: दिसंबर, 2020 – जनवरी, 2021) आयोजित किए ।

8. SARS-CoV-2 / COVID-19 के निदान, स्क्रीनिंग-संपर्क और हॉट स्पॉट की पहचान के लिए सभी द्वीपों के लिए प्रदान किए गए असाधारण योगदान को देखते हुए आईसीएमआर-आरएमआरसीपीबी (क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र पोर्ट ब्लेयर) को उपराज्यपाल प्रशस्ति प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया गया।

9. आईसीएमआर ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू), अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली (एम्स) और आईसीएमआर-राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान सांख्यिकी संस्थान (आईसीएमआर-एनआईएमएस) के सहयोग से COVID-19 के लिए एक राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री (NCRC) शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में फैले 42 अस्पतालों में अस्पताल में भर्ती COVID-19 रोगियों की नैदानिक और प्रयोगशाला विशेषताओं, उपचारों और परिणामों के बारे में डेटा एकत्र करना है। दैनिक परीक्षण इस हद तक काफी बढ़ गया कि मार्च 2021 तक, 244 मिलियन नमूनों की जांच की गई।

10. आईसीएमआर-एनआईवी (राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान), पुणे ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत रियल टाइम 168 RT-PCR किटों, 164 RNA निष्कर्षण किट, 99 VTM और स्वैब का मूल्यांकन किया; मान्य ट्रूनेट बीटा CoV E-जीन स्क्रीनिंग परख और ट्रूनेट SARS-CoV-2 RdRp जीन की जांच के पुष्टिकरण (मोल्बियो डायग्नोस्टिक्स, भारत); SARS-CoV-2 के लिए 225 वाणिज्यिक सेरोडायग्नॉस्टिक किट (रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, एलिसा और सीएलआईए) का मूल्यांकन किया गया और छियालीस उत्पादकों को मान्यता दी गई; SARS-CoV-2 वायरस के सतही परिशोधन के लिए ओजोन और नगेटिव आयन पीढ़ी प्रणालियों पर आधारित तीन व्यावसायिक प्रौद्योगिकियों में से दो को मान्यता प्रदान की गई।

11. भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा COVID-19 परीक्षण सुविधा में एक उच्च थ्रूपुट COBAS8800 स्वचालित प्रणाली का उद्घाटन किया गया था जिसने SARS-CoV-2 के लिए नमूनों की जांच की क्षमता को

काफी बढ़ा दिया। आईसीएमआर ने तीनों सत्रों के दौरान भारत के सांसदों के कोविड-19 परीक्षण को समन्वित किया।

12. भारत ने आपातकालीन समीक्षा के लिए एसओपी के साथ-साथ COVID-19 महामारी के दौरान अनुसंधान की समीक्षा करने वाली नैतिकता समितियों के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश भी विकसित किए। भारत में COVID-19 से संबंधित मौतों की उचित रिकॉर्डिंग के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज विकसित किया गया था ताकि COVID-19 के कारण होने वाली मौतों की सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जा सकें।

13. आईसीएमआर - आरएमआरसीपीबी (क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र पोर्ट ब्लेयर) कार निकोबार की निकोबारी जनजाति के बीच क्षय रोग के नियंत्रण पर भी कार्य कर रहा है। न्यूनतम संसाधन प्रणाली पर लेप्टोस्पायरोसिस का शीघ्रता से निदान करने के लिए एक ट्रूनेट - माइक्रो रियल टाइम-पीसीआर का मूल्यांकन किया गया था। केंद्र ने नई रणनीति के लाभ का भी प्रदर्शन किया जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमडीए) को बड़े पैमाने पर डबल फोर्टिफाइड नमक (डीईसी + आयोडीन) के साथ पूरक करता है ताकि दो द्वीपों में दैनिक उप-आवधिक वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी का उन्मूलन किया जा सके।

14. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अंतरक्षेत्रीय समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से "जूनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अंतरक्षेत्रीय समन्वय का सुदृढ़ीकरण" योजना शुरू की।

15. आईसीएमआर-एनआईएन (राष्ट्रीय पोषण संस्थान), हैदराबाद ने भारतीयों के लिए नवीनतम पोषक तत्वों की आवश्यकताओं और अनुशंसित आहार भत्तों को जारी किया। भारत क्या खाता है? रिपोर्ट ने पहली बार, पहले के आहार सर्वेक्षणों के डेटा का विश्लेषण किया और खाद्य समूहों के आधार पर अनुमानित देश भर में आहार के तरीकों का अवलोकन प्रदान किया।

16. जैसाकि सरकार "मुद्रीकरण और आधुनिकीकरण" के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, आईसीएमआर ने "प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और राजस्व साझाकरण हेतु दिशा-निर्देश" तैयार किएं हैं। ये दिशा-निर्देश एक ऐसे ढांचे के माध्यम से आईसीएमआर प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने का प्रयास करते हैं जो सरकार की मेक-इन-इंडिया पहल के अनुसार स्वदेशी उत्पाद विकास और व्यावसायीकरण के लिए अग्रणी उद्योग/उद्योगों को प्रौद्योगिकी का निर्बाध हस्तांतरण सुनिश्चित करते है।

17. कुष्ठ डाटा प्रबंधन प्रणाली (निकुष्ट) को राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) को सौंप दिया गया है। जल जीवन मिशन के लिए वेब-आधारित और मोबाइल ऐप समाधान राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है, ताकि वर्ष 2024 तक गांवों के हर घर में नल के कनेक्शन उपलब्ध हो सकें। आईसीएमआर-एनआईवी, पुणे में रेबीज निदान और अनुसंधान के लिए एक केंद्र स्थापित किया गया था।

इस अवधि के दौरान, आईसीएमआर ने पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में सेंटर फॉर इनोवेशन एंड बायो-डिज़ाइन (CIBID) भी शुरू किया है, जो इस नई अवधारणा को साझा करने और नवीन और पेटेंट-उन्मुखी अनुसंधान को प्रस्तुत करने के लिए चिकित्सकों और डोमेन विशेषज्ञों को सहयोग करने के लिए एक मंच तैयार करेगा। केंद्र ने नवाचार और उद्यमवृत्ति (PIE) कार्यक्रम का प्रसार शुरू कर दिया है तथा 'ई-अविष्कार' नाम का

एक जर्नल भी शुरू किया है। आईसीएमआर ने स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी त्वरित व्यावसायीकरण (एचटीएसी) कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के व्यावसायीकरण के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के साथ एक समझौता किया। एचटीएसी कार्यक्रम के तीन घटक - व्यावसायीकरण घटक, प्रशिक्षण घटक और प्रदर्शनी घटक हैं।

19. आईसीएमआर ने "चिकित्सक / दंत विशेषज्ञ / पैरा मेडिकल संस्थानों / कॉलेजों और संबद्ध जैव चिकित्सा अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों में चिकित्सा पेशेवरों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए नवाचार और उद्यमिता के लिए नीति दस्तावेज" तैयार किया है। यह पहल देश में चिकित्सा उपकरण नवाचारों को बढ़ावा देगी और इस प्रकार भारत सरकार की मेक-इन-इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्ट-अप-इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा।

20. कुल 15 पेटेंट हेतु आवेदन भरे गए, 4 भारतीय पेटेंट और 2 विदेशी पेटेंटों को मंजूरी प्रदान की गई। कुल 36 पेटेंट बनाए गए थे। आईसीएमआर ने "मेडिकल डिवाइस एंड डायग्नोस्टिक्स मिशन सचिवालय (MDMS)" की स्थापना की है। यह अभिनव प्रौद्योगिकी विकास, कौशल विकास को बढ़ावा देगा और भारत की आयात निर्भरता को कम करने के लिए चिकित्सा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर और आईआईटी हैदराबाद में दो बायोडिज़ाइन कार्यक्रम शुरू किए गए।

21. कुल 773 तदर्थ प्रस्ताव, 815 फैलोशिप और 237 डीएचआर-जीआईए प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई। जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में आईसीएमआर के 14 विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कारों/ईनामों से कुल 21 वैज्ञानिकों और 14 युवा शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया। आईसीएमआर की महिला योद्धाओं पर एक विशेष संस्करण प्रकाशित किया गया था। आईसीएमआर की इतिहास समयरेखा विकसित की गई जो कि 1911 में परिषद की स्थापना के दिन से परिषद की 108 वर्ष की यात्रा को दर्शाती है।

22. COVID-19 महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए आईसीएमआर- राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईसीपीआर), नोएडा में डब्ल्यूएचओ एफसीटीसी ग्लोबल नॉलेज हब ऑन स्मोकलेस टोबैको ने तंबाकू नियंत्रण और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अपील जारी की, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने तंबाकू को नियंत्रित करने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक परामर्श जारी किया है। आईसीएमआर-एनआईसीपीआर ने लेह में कोविड-19 हेतु परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अधिप्रमाणित

(डॉ. भारती प्रविण पवार)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री

डॉ. भारती प्रविण पवार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री
भारत सरकार